

Title: Requested to set up a parliamentary committee to investigate into the deteriorating law and order situation in Bihar with special reference to police atrocities on the students and innocent people at Imamganj.

श्री अरूण कुमार (जहानाबाद) : महोदय, अभी 19 तारीख को बिहार के इमामगंज में जिस तरह समानांतर सरकार चल रही है और नक्सली संगठनों ने वहां के विद्यार्थियों को जन-अदालत में सजा दी, इस कारण से स्कूल के विद्यार्थियों ने रोड़ जाम किया और प्रशासन को इसकी और इंगित कराने का काम किया। इसी बीच पटना जिले की पुलिस ने स्कूली छात्रों पर जिस तरह गोली और लाठी का प्रयोग किया, उससे आठ-13 और एक 18 वर्षीय बच्चा पुलिस की लाठी का शिकार हुआ। उन्हें नदी में पानी में डाल दिया गया। पुलिस की क्रूरता इस हद तक हुई है कि जब पूरे इलाके के लोग लाश तलाशने में पानी में जाना चाहते थे तो पुलिस ने बेरहमी से वहां के लोगों को मारा-पीटा। तीन दिन के बाद जब पूरे इलाके को घेर लिया तब लाश बरामद हुई। अब स्कूली छात्रों को भी वहां की बर्बर पुलिस सहन नहीं कर पा रही है। इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि वहां जो समानांतर सरकारें चल रही हैं और जिस तरह पुलिस बेलगाम हो गई है, उस पर यहां कमेटी बनाई जाए। जिस तरह वहां दलित महिलाओं और छात्रों के साथ पुलिस बेरहमी के साथ कार्यवाही कर रही है, निरंकुशता चला रही है, **टी।ए। (व्यवधान)** महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है, इसलिए संसदीय कमेटी बना कर पूरे मामले की जांच कराई जाए। **टी।ए। (व्यवधान)**

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : महोदय, मैं भी इससे अपने को संबद्ध करती हूं। मेरा नाम है, मैंने नोटिस भी दिया है। वहां इतना ही नहीं हुआ है बल्कि जो औरत लाश को लेकर वहां घेराव करने के लिए गई थी, उसे भी पीटा गया।

अध्यक्ष महोदय: आप भी इसमें एसोशिएट कर सकती हैं।

श्रीमती रेनु कुमारी : क्या उस महिला को इतना भी अधिकार नहीं है कि वह अपने मरे हुए बच्चे के साथ लिपट कर रोए। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाए। चाहे इसके लिए वहां की सरकार दोगी हो, या पुलिस पदाधिकारी दोगी हों या कोई और हो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया में इससे बढ़ कर दूसरा कोई अन्याय नहीं है। जिस तरह बिहार में जुल्म हो रहे हैं, उसे देखते हुए वहां की सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उनकी सरकार को समर्थन देने वाले भी उतने ही दोगी हैं। यदि केन्द्र सरकार संवेदनशील है तो एक जांच कमेटी नियुक्त कर और न्याय दिलवाए। **टी।ए। (व्यवधान)**